साप्ताहिक
युवा प्रदेश
Freedom Of Speech
RNI. NO. MPHIN/2015/76299
संपादक-नागेश नरवरिया
YP24 NEWS
जिले एवं तहसीलों में संवाददाता नियुक्त करना है संपर्क करें ...
संपर्क करे- 9425156055
वर्ष-10 अंक-02 | www.yuvapradesh.in | भोपाल, शुक्रवार 27 फरवरी 2026 | ypnews24@gmail.com | पृष्ठ-08 | मूल्य 2 रूपये

Powers of Supreme Court
सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों में अभिलेख न्यायालय का अर्थ क्या है पढ़िए

भारत में कानून बनाने की शक्ति केवल संसद के पास है परंतु संसद द्वारा बनाए गए कानून को निरस्त करने की ताकत सुप्रीम कोर्ट के पास है। सिर्फ इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट इतना ताकतवर है कि उसके आदेश, विधि के

रूप में मान्य होते हैं और पूरे देश में लागू होते हैं। आइए भारतीय लोकतंत्र के सबसे शक्तिशाली और जिम्मेदार स्तंभ की सबसे खास बात बताते हैं

भारत में किसी भी कानून को बनाने के लिए संसद के सत्र का आयोजन किया जाता है। लोकसभा एवं राज्यसभा में विधेयक पेश किया जाता है। संसद के दोनों सदनों में सदस्यगण उस पर विचार विमर्श करते हैं और आवश्यक होने पर संशोधन भी किया जाता है तत्पश्चात उसे राष्ट्रपति महोदय के पास भेजा जाता है। भारत के राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाने के बाद वह विधेयक, कानून बन जाता है और गजट नोटिफिकेशन के साथ लागू हो जाता है। कुल मिलाकर एक कानून बनाने में इतनी लंबी प्रक्रिया का पालन करना होता है लेकिन इससे कहीं अधिक शक्तिशाली होता है। वह न केवल संविधान का उल्लंघन करने वाले कानूनों को शून्य घोषित कर सकता है बल्कि उसके कुछ आदेश कानून बन जाते हैं। अभिलेख न्यायालय भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र एवं एकीकृत न्यायपालिका हैं एवं यह लोकतंत्र का सर्वोच्च अंग हैं। जब कोई निर्णय, जजमेंट, आदेश, या ऑडर उच्चतम न्यायालय सुना देता है तब वह फैसला एक साक्ष्य के रूप में माना जायेगा एवं वह कानून, विधि बन जाएगा अर्थात उच्चतम न्यायालय की %अभिलेख न्यायालय% की शक्ति वह शक्ति है जिसमे उच्चतम न्यायालय के किसी भी फैसले को किसी भी जिला कोर्ट, हाईकोर्ट में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय का फैसला एक विधि माना जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत की न्यायपालिका स्वतः ही एक सर्व-शक्तिशाली हैं

लेखक एडवोकेट बी. आर. अहिरवार (विधिक सलाहकार नर्मदापुरम) 9827737665*

उज्जैन के दर्शनीय स्थलों के पिक्टोरियल पोस्टकार्ड का किया विमोचन

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारतीय डाक व्यवस्था में आये निर्णायक परिवर्तन : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

भारत साम्राज्य, भोपाल।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि नागरिकों के हित में भारतीय डाक व्यवस्था ने अपनी सार्थक भूमिका सिद्ध की है। ब्रिटिश काल से प्रारंभ व्यवस्थाओं को नया स्वरूप मिलता गया। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में डाक व्यवस्था में निर्णायक परिवर्तन आये हैं और डाक विभाग की भूमिका को महत्वपूर्ण बनाने की ठोस पहल हुई है। एक समय सिर्फ चिट्ठियां पहुंचाने वाला विभाग अब बाबा महाकाल के प्रसाद के वितरण के लिए नई पोस्टल सेवा लागू करने तक अपनी यात्रा तय कर चुका है। डाक घरों के माध्यम से नागरिकों को बीमा योजनाओं, बचत योजनाओं का लाभ मिल रहा है। खाते प्रारंभ करने से लेकर तीव्र गति से स्पीड पोस्ट और अन्य माध्यमों से ग्राहकों को लाभान्वित किया जा रहा है। ग्रामीण डाक सेवक भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूत नींव है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव मंगलवार को उज्जैन में शिप्रा नदी किनारे स्थित कार्तिक मेला ग्राउंड में आयोजित ग्रामीण डाक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय संचार मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने डाक सेवकों का अभिनंदन करते हुए कहा कि अपने अथक परिश्रम से गांव-गांव तक डाक तथा अन्य जनउपयोगी सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने वाले ग्रामीण डाक सेवकों की देश के निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कार्यक्रम में मध्यप्रदेश के उत्कृष्ट कार्य करने वाले ग्रामीण डाक नायकों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव और केंद्रीय मंत्री श्री सिंधिया के द्वारा भारतीय डाक विभाग से उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर तथा श्री ओंकारेश्वर ज्योर्तिलिंग मंदिर की प्रसादी आमजन तक पहुंचाने के लिए पोस्टल सेवा का शुभारंभ किया गया।

उज्जैन में ग्रामीण डाक सेवक सम्मेलन द्यमें डाक नायकों का किया सम्मान

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि ग्रामीण डाक सेवक हमारे सैनिक तथा हमारी ताकत है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में डाक विभाग सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है। हमारे देश में प्राचीन काल से ही डाक पहुंचाने की परंपरा रही है। हमारे देश में डाक सेवकों का हृदय से सम्मान रहा है। बदलते दौर में देश के पोस्ट ऑफिस तीव्र गति से कार्य कर रहे हैं। डाक विभाग को तकनीकी रूप से दक्ष बनाया जा रहा है। विभाग को शत प्रतिशत कम्प्युटरीकृत तथा डिजिटलाईज किया जा रहा है। आमजन के हित में दिन रात अपनी भूमिका को सराहनीय रूप से निभाने के लिए हमारा डाक विभाग बधाई का पात्र है। सूचनाओं को जन-जन तक पहुंचाने के अलावा अन्य कई महत्वपूर्ण जीवन उपयोगी कार्यों में भी डाक विभाग की महती भूमिका है। श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में डाक विभाग नई ऊंचाइयों को छू रहा है। मध्यप्रदेश में 16 हजार 800 से ज्यादा ऊर्जावान ग्रामीण डाक सेवक ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने का काम कर रहे है। केंद्रीय संचार मंत्री श्री सिंधिया ने कहा कि सभी ग्रामीण डाक सेवक मेरे परिवार के सदस्य हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में डाक विभाग देश के विकास में अपनी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहा है। डाक विभाग को तकनीकी रूप से सुदृढ बनाने के लिए कई कदम उठाए गए है। हमारा संकल्प है कि देश के डाक विभाग को विश्व की सबसे बड़ी लाजिस्टिक शक्ति के रूप में स्थापित करेंगे। केन्द्रीय मंत्री श्री सिंधिया ने कहा कि देश में ग्रामीण डाक सेवक एक सैनिक की भांती कार्य कर रहे हैं। रेगिस्तान हो या पहाड़ों की चोटियां या मैदानी क्षेत्र हर एक स्थान पर ग्रामीण डाक सेवक निर्भीक रूप से पहुंचकर आमजन की सेवा कर रहे है।

2 मार्च से थम सकते हैं बसों के पहिएः नई परिवहन नीति के विरोध में प्रदेशव्यापी हड़ताल का ऐलान

कैलाश कुमार अहिरवार - सह संपादक (युवा प्रदेश)

मध्य प्रदेश में नई परिवहन नीति को लेकर बस संचालकों और सरकार के बीच टकराव गहराता जा रहा है। शहडोल जिला बस ओनर्स एसोसिएशन ने प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में लागू किए गए परिवहन नीति संशोधनों के विरोध में 2 मार्च 2026 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की घोषणा कर दी है। इस फैसले के बाद पूरे प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था ठप होने की आशंका जताई जा रही है। बस संचालकों का आरोप है कि 24 दिसंबर 2025 और 29 जनवरी 2026 को राजपत्र में प्रकाशित संशोधन 'स्टेज कैरेज' बसों के संचालन के लिए अत्यंत कठोर और अव्यावहारिक हैं। उनका कहना है कि नई शर्तों के तहत बस संचालन करना

आर्थिक रूप से संभव नहीं रहेगा, जिससे हजारों परिवारों की रोजी-रोटी पर संकट खड़ा हो जाएगा। एसोसिएशन का स्पष्ट मत है कि सरकार को पूर्व में लागू व्यवस्था को यथावत रखते हुए नए संशोधनों को तत्काल प्रभाव से वापस लेना चाहिए।

सागर में आयोजित प्रदेश स्तरीय बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि यदि शासन 2 मार्च तक सकारात्मक पहल नहीं करता है, तो प्रदेशभर के बस संचालक अपने वाहनों का संचालन बंद कर देंगे। एसोसिएशन पदाधिकारियों का कहना है कि उन्होंने कई बार अधिकारियों के समक्ष अपनी समस्याएं रखीं, लेकिन समाधान की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि हड़ताल के कारण आमजन को असुविधा होती है तो इसकी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।

इसी क्रम में शहडोल जिला बस ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष भगवत प्रसाद गौतम (महंत गौतम) और सचिव देवेन्द्र मिश्रा के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान हसीब खान टीपू, विनय सिंह मोनू सहित बड़ी संख्या में बस संचालक उपस्थित रहे। ज्ञापन के माध्यम से सरकार को चेतावनी दी गई कि मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। यदि हड़ताल होती है तो इसका सीधा असर छात्रों, नौकरीपेशा लोगों, ग्रामीण क्षेत्रों के यात्रियों और छोटे व्यापारियों पर पड़ेगा। प्रदेश की यातायात व्यवस्था पर संभावित संकट को देखते हुए अब सबकी नजरें सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं। आने वाले कुछ दिन यह तय करेंगे कि विवाद वार्ता से सुलझेगा या प्रदेश में सचमुच बसों के पहिए थम जाएंगे।

ऊंच-नीच अउ भेद-भाव मा,
तुंहर धरम के महल खड़े हे।
चार बरन अउ जाति भेद के,
ओमा गहरा रंग चढ़े हे।।
धरम के ठेका अउ मंदिर के,
अपन आरक्षन ला बचाना हे।
भेदभाव तुम जारी रखहू,
ऊपरी छावा बोमियाना हे।।
लक्ष्मी नारायण कुम्भकार सचेत दुर्ग (छ0ग0)

पहली बार ऑनलाइन ऐप से प्रदेश व्यापी गिद्ध गणना के लिए कर्मचारियों को ऑनलाईन प्रशिक्षण दिया गया

रिपोर्टर देवेन्द्र कुमार जैन भोपाल मध्य प्रदेश

प्रदेश व्यापी गिद्ध गणना 2025-26 में शीतकालीन गणना 20 फरवरी से 22 फरवरी 2026 तक सूर्योदय से सुबह 9.00 बजे तक प्रदेश के सभी 16 वृत्त एवं 9 टाईगर रिजर्व में गिद्ध गणना का कार्य वन विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों, डब्लू डब्लू.एफ., डब्लू.आई.आई. के प्रतिभागियों के अतिरिक्त स्वंय सेवक एवं फोटोग्राफरों के द्वारा मिलकर किया जा रहा है। मध्यप्रदेश में प्रदेशव्यापी गिद्ध गणना की शुरूआत वर्ष-2016 से की गई थी जिसमें 7,028 गिद्धों का आंकलन किया गया था। गिद्ध गणना वर्ष-2025 में शीतकालीन गणना में 12710 एवं ग्रीष्मकालीन गणना वर्ष-2025 में 9509 गिद्धों का आंकड़ा प्राप्त हुआ था।मध्यप्रदेश में कुल 7 प्रजातियों के गिद्ध पाये जाते हैं, जिसमें से 4 प्रजातियों स्थानीय हैं एवं 3 प्रजातियाँ प्रवासी हैं, जो ठंड के समाप्त होते ही वापस चली जाती हैं। प्रथम चरण की गणना तब की जाती है जब उपरोक्त सभी प्रजातियों के गिद्ध घोंसले बनाकर अपने अंडे दे चुके होते हैं या देने की तैयारी में होते हैं। इसी प्रकार से फरवरी माह आने तक इन घोंसलों में अंडों से नवजात गिद्ध निकल चुके होते हैं तथा वे उड़ने की तैयारी करते होते हैं। इसलिये गणना करने के लिये शीत ऋतु का अंतिम समय उचित होता है जिससे स्थानीय तथा प्रवासी गिद्धों की गणना हो जाए। इस बार गिद्धों की गणना के लिये प्रथम बार ऑनलाइन ऐप तयार किया गया है, जिसके माध्यम से गिद्धों की गणना की जा रही है। ÷ऐप÷ के माध्यम से गणना किये जाने पर आंकड़ों के संकलन एवं रिपोर्ट तैयार करने में आसानी होगी। गत वर्षों में गणना ऑफलाइन की जाती रही है। ऐप के माध्यम से गणना किये जाने के लिये मास्टर ट्रेनर्स, अशासकीय संस्थाओं एवं अधिकारियों कर्मचारियों को ऑनलाईन प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। गिद्धों की गणना के लिये गणनाकर्मी एवं स्वयंसेवक आदि सूर्योदय के तत्काल बाद प्रथम चरण में चयनित गिद्धों के घोंसलों के समीप पहुंच जाएंगे और घोंसलों के आसपास बैठे गिद्धों एवं उनके नवजातों की गणना ऐप के माध्यम से करेंगे। गणना के दौरान इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि केवल आवास विश्राम स्थलों पर बैठे हुए गिद्धों को ही गणना में लिया जाए। उड़ते हुए गिद्धों को गणना में नहीं लिया जाता है। इस वर्ष वन विभाग के कर्मचारियों के साथ-साथ पूरे प्रदेश के विभिन्न स्थानों में पक्षी विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, छात्र, फोटोग्राफर एवं स्थानीय नागरिक इस गणना में भाग ले रहे हैं। गणना उपरांत डाटा संकलन का कार्य वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में किया जावेगा।

असंगठित श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण होगा म.प्र. असंगठित शहरी एवं ग्रामीण कर्मकार कल्याण मंडल की चतुर्थ बैठक

रिपोर्टर देवेन्द्र कुमार जैन भोपाल मध्य प्रदेश

मध्यप्रदेश में असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों का ÷मुख्यमंत्री श्रम श्री÷ स्वास्थ्य अभियान के अंतर्गत स्वास्थ्य परीक्षण कर डिजिटल हेल्थ रिकार्ड रखा जायेगा, विशेष रूप से श्रमिकों के 25 वर्ष से कम उम्र के बच्चों तथा 50 वर्ष से अधिक उम्र के श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण प्राथमिकता से किया जायेगा। इस कार्य में पंचायतों में संचालित आयुष भवनों का भी सहयोग लिया जायेगा। यह निर्णय प्रदेश के श्रम मंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल की अध्यक्षता में म.प्र. असंगठित शहरी एवं ग्रामीण कर्मकार कल्याण मंडल की चतुर्थ बैठक में लिये गये। इस अवसर पर मंडल के आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट प्राक्कलन को स्वीकृति प्रदान की गई। श्रम मंत्री द्वारा प्रथम श्रमणा सहकारी समिति, भोपाल के अध्यक्ष तथा समिति के सदस्यों का टी-शर्ट, कैप तथा प्रमाण-पत्र प्रदान कर स्वागत किया गया।असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को श्रमणा योजना अंतर्गत सहकारी समिति बनाकर स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ने के लिये अवसर प्रदान करने के लिये एक करोड़ राशि का प्रावधान मंडल के बजट में करने का निर्णय लिया गया। संबल कार्ड के नवीनीकरण के लिये श्रमिकों से शुल्क लिये जाने तथा नियोजकों से अभिदाय लेकर असंगठित श्रमिकों के लिये कल्याण निधि गठित करने के प्रस्ताव पर चर्चा की गई। बैठक में प्रदेश के असंगठित क्षेत्र में कार्यरत 1 करोड़ 78 लाख श्रमिकों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से जोड़े जाने एवं श्रमिकों एवं उनके आश्रितों को रोजगारपरक कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध करवाने के लिये योजना पर विचार किया गया। असंगठित श्रमिकों के पुत्र-पुत्रियों को जो 10वीं की परीक्षा में प्रावीण्य सूची में रहे है. ऐसे 100 छात्रों को छात्रवृत्ति उच्च शिक्षा स्तर तक दिये जाने के संबंध में योजना तैयार करने का निर्णय लिया गया।

युद्ध स्तर पर करें सीएम हेल्पलाइन शिकायतों का निराकरण समीक्षा बैठक में निर्देश

रिपोर्टर देवेन्द्र कुमार जैन भोपाल मध्य प्रदेश

कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभाकक्ष में समय-सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर 50 दिवस से लंबित शिकायतों का निराकरण नहीं करने पर साथ ही अन-अटेन्डेंट एवं पुअर डिस्पोजल के लिए सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। सभी एसडीएम एवं तहसीलदारों को राजस्व विभाग फॉर्मर रजिस्ट्री नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन के लिए युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर प्रकरणों में तेजी एवं पारदर्शिता के साथ प्रगति लाने के निर्देश देते हुए कहा कि इन कार्यों के प्रभावी निष्पादन से भोपाल जिले की रैंकिंग में उल्लेखनीय सुधार लाया जाए।कलेक्टरङ्ककमिश्नर कॉन्फ्रेंस के पालन प्रतिवेदन के संदर्भ में सभी विभागों को निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप ठोस प्रगति सुनिश्चित करने तथा नियमित मॉनिटरिंग के माध्यम से परिणामोन्मुखी कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी एसडीएम, तहसीलीदार कोर्ट व्यवस्थित करने के निर्देश दिए। साथ ही आगामी दिनों में फसल कटाई के बाद पराली जलाने की एक भी घटना न होने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में किसानों को संबंधित विभागों के अधिकारियों अभी से जागरूक करने एवं पराली के लिए अन्य विकल्पों रोटा वेटर, हैप्पी सीडर अपनाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही आगामी दिनों में त्यौहारों को देखते हुए लॉ एंड आर्डर के साथ आगजनी की घटनाओं को रोकने के लिए संबंधित दलों के साथ बैठक कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। नगर निगम के अधिकारियों को समग्र, ई-केवायसी के कार्य में तेजी लाने के भी निर्देश दिए गए।

अमरकंटक में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरों की श्रृंखला-हर रविवार विशेषज्ञों की सेवाएं

श्री चंद्राचार्य धर्मार्थ चिकित्सालय द्वारा मिर्गी, मधुमेह, स्त्री रोग, अस्थि व शिशु रोग पर विशेष परामर्श व दवाएं निःशुल्क

अमरकंटक।

मां नर्मदा जी की उद्गम स्थली/पवित्र नगरी अमरकंटक स्थित कल्याण सेवा आश्रम द्वारा संचालित श्री श्रीचंद्राचार्य धर्मार्थ चिकित्सालय विगत कई वर्षों से क्षेत्रवासियों को निरंतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहा है । चिकित्सालय में 24 घंटे आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है । चिकित्सालय के तत्वावधान में प्रत्येक माह निःशुल्क विशेष स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जा रहा है जिसमें विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा रोगियों की जांच , आवश्यक परामर्श तथा दवाएं पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं । प्रत्येक रविवार को अलग-अलग रोगों से संबंधित शिविर आयोजित किए जाएंगे ।

मासिक शिविरों की रूपरेखा इस प्रकार है=

1 मार्च - प्रथम रविवार – मिर्गी , लकवा व स्नायु रोग

चिकित्सक= डॉ. रजनीश पांडेय (बिलासपुर)

8 मार्च ङ्क द्वितीय रविवार – मधुमेह (शुगर) , उच्च रक्तचाप , सिकलसेल व मानसिक रोग चिकित्सक= डॉ. योगेन्द्र परिहार (बिलासपुर), डॉ. शकुंतला लांझी (अमरकंटक), डॉ. एस.के. घर (बिलासपुर), डॉ. अभिषेक पांडेय, डॉ. मनोज मेरगो

15 मार्च - तृतीय रविवार – स्त्री रोग विशेष शिविर

चिकित्सक=डॉ. इशिता प्रियदर्शिनी , डॉ. वर्षा नरेटी , डॉ. मीनाक्षी (स्त्री रोग विशेषज्ञ)

22 मार्च - चतुर्थ रविवार – अस्थि एवं शिशु रोग शिविर

चिकित्सक=डॉ. वैभव कौशिक (अस्थि रोग विशेषज्ञ) , डॉ. अंकित शाह, डॉ. चंद्र प्रकाश, डॉ. बलदेव (शिशु रोग विशेषज्ञ)

आगामी विशेष शिविर=

01 मार्च 2026 (रविवार)= मिर्गी रोग विशेष शिविर

08 मार्च 2026 (रविवार)= मधुमेह (शुगर) रोग विशेष शिविर

सभी स्वास्थ्य शिविर प्रातः 10=00 बजे से दोपहर 1=00 बजे तक आयोजित किए जाएंगे। शिविर पूर्णतः निःशुल्क रहेंगे जबकि अन्य दिनों में चिकित्सालय के नियमानुसार शुल्क देय होगा । अधिक जानकारी हेतु संपर्क= 8839037328 , 9329293579

चिकित्सालय प्रबंधन द्वारा क्षेत्रवासियों से अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लेने की अपील की गई है ।

कलेक्टर ने जिला अस्पताल का सुबह की ओपीडी में दी जा रही सेवाओं का औचक निरीक्षण किया

रिपोर्टर देवेन्द्र कुमार जैन भोपाल मध्य प्रदेश

जयप्रकाश जिला चिकित्सालय की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए कलेक्टर भोपाल कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने सुबह की ओपीडी में दी जा रही सेवाओं का औचक निरीक्षण किया। जिसमें बाह्य रोग विभाग, पंजीयन व्यवस्था, एक्स-रे, फिजियोथैरेपी सहित कई विभागों की सेवाओं को देखा। फिजियोथैरेपी यूनिट में मरीजों की कम संख्या मिलने पर फिजियोथैरेपी सेवाओं की जानकारी प्रदर्शित करने और यूनिट के आवश्यकता अनुसार उन्नयन को प्रस्तावित करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान एक्स-रे करवाने के लिए मरीजों की लंबी कतार को देखकर उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए टोकन या सिरियल

नंबर से एक्स-रे करने के निर्देश दिए। ओपीडी पंजीयन में भी मरीजों की अधिक संख्या को देखते हुए विशेष रूप से वृद्ध और गंभीर बीमारियों के मरीजों की बैठक व्यवस्था करने के निर्देश दिए। सिविल सर्जन से कहा कि वे गुणवत्तापूर्ण उपचार के साथ-साथ यह भी सुनिश्चित करें कि अस्पताल आने वाले मरीज को कम से कम समय में उपचार मिल सके। उच्च रक्तचाप, डायबिटीज के उपचार और फॉलोअप सहित विभिन्न सामान्य व मौसमी बीमारियों के इलाज की सुविधा मुख्यमंत्री संजीवनी क्लीनिक में उपलब्ध है। उन्होंने सीएमएचओ को निर्देश दिए कि जिला चिकित्सालय के ओपीडी लोड को कम करने के लिए मुख्यमंत्री संजीवनी क्लीनिक से सामान्य बीमारियों के उपचार के लिए स्थानीय स्तर से प्रेरित किया जाए।

कर्ज के बोझ तले टूटी जिंदगी: शहडोल के जंगल में फांसी पर लटका मिला युवक का शव, किस्तों के दबाव में उठाया कदम

संभागीय संवाददाता -राजू राय

एक युवक का शव फांसी के फंदे से लटका मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। यह घटना चूंदी नदी के पास हाइवे से करीब 100 मीटर अंदर जंगल में सामने आई। सूचना मिलते ही गोहपारू पुलिस मौके पर पहुंची और मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है।शहडोल जिले के गोहपारू थाना क्षेत्र में एक युवक का शव फांसी के फंदे से लटका मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। यह घटना चूंदी नदी के पास हाइवे से करीब 100 मीटर अंदर जंगल में सामने आई। सूचना मिलते ही गोहपारू पुलिस मौके पर पहुंची और मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान दिनेश प्रताप सिंह गोंड (25) निवासी धौनहा के रूप में हुई है। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि युवक ने वाहन के नाम पर लोन लिया था और वह लंबे समय से कर्ज के बोझ तले दबा हुआ था। परिजनों और स्थानीय लोगों ने बताया कि उस पर लाखों रुपये का कर्ज था।

किस्तें जमा नहीं हो पाने के कारण कर्जदार बार-बार घर पहुंचकर दबाव बना रहे थे, जिससे वह मानसिक रूप से काफी परेशान रहने लगा था।पुलिस के मुताबिक 18 फरवरी को दिनेश पैसे की व्यवस्था करने की बात कहकर घर से निकला था, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटा। 19 फरवरी को उसकी अंतिम बार परिजनों से फोन पर बातचीत हुई थी, जिसके बाद से उसका मोबाइल बंद हो गया और वह लापता हो गया। परिवार वाले उसकी तलाश कर रहे थे, तभी सोमवार देर शाम स्थानीय लोगों ने जंगल के अंदर एक युवक का शव फांसी के फंदे से लटकता देखा और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतरवाकर पंचनामा कार्रवाई की और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मंगलवार सुबह मर्ग कायम कर मामले की विस्तृत विवेचना शुरू कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों की पुष्टि हो सकेगी।

पुणे से बरामद हुई गुमशुदा नाबालिग, बिजुरी पुलिस की तत्परता से परिजनों को सौंपा गया विशेष टीम की सक्रियता और तकनीकी सहायता से मिली सफलता

अनूपपुर।

बिजुरी पुलिस ने गुमशुदा नाबालिग बालिका को सकुशल दस्तयाब कर परिजनों के सुपुर्द कर सराहनीय कार्य किया है। पुलिस अधीक्षक मोती उर्र रहमान के निर्देश पर नाबालिग बालक-बालिकाओं की शीघ्र दस्तयाबी हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जगन्नाथ मरकाम एवं एसडीओपी आरती शाक्य के मार्गदर्शन में कार्रवाई की गई। प्रकरण के अनुसार 20 जनवरी 2026 को फरियादिया ने थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी नाबालिग पुत्री 19 जनवरी की सुबह लगभग 7-30 बजे गाय ढीलने का कहकर घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। आसपास व रिश्तेदारी में तलाश के बाद भी कोई पता नहीं चला। रिपोर्ट पर धारा

137(2) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई।

विवेचना के दौरान पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विशेष टीम गठित की गई। लगातार प्रयास, सुरागरसी, मुखबिर सूचना एवं तकनीकी सहायता के आधार पर 23 फरवरी 2026 को नाबालिग बालिका को पुणे (महाराष्ट्र) से सकुशल बरामद कर लिया गया। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई के बाद बालिका को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया।

बालिका की सुरक्षित वापसी से परिवार में खुशी का माहौल है और परिजनों ने पुलिस के प्रति आभार व्यक्त किया है।

इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक विकास सिंह की अगुवाई में विपिन बिहारी राय, सुनील यादव, आनन्द, संगम तोमर तथा साइबर सेल के पंकज की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

डूमरकछार निकाय में संविलियन पर संगीन आरोप: नियुक्ति शर्तों की अनदेखी, फर्जीवाड़े व गबन की जांच की मांग तेज

राजनगर कालरी/अनूपपुर।

नवगठित नगर परिषद डूमरकछार में पंचायत कालीन कर्मचारियों के संविलियन को लेकर गंभीर अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं। निकाय अध्यक्ष सहित कई निर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने सक्षम अधिकारियों से शिकायत कर जिला चयन समिति (06.02.2021) के निर्णय, नियुक्ति शर्तों के पालन और वित्तीय लेनदेन की उच्चस्तरीय जांच की मांग की है आरोप है कि तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव रजनीश प्रसाद शुक्ला का राजस्व उपनिरीक्षक पद पर संविलियन नियमों के विरुद्ध किया गया। नियुक्ति आदेश में तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि के दौरान एलएसजीडी

डिप्लोमा अनिवार्य बताया गया था, अन्यथा मूल पद पर वापसी का प्रावधान था। शिकायतकर्ताओं का दावा है कि डिप्लोमा प्राप्त न करने के बावजूद आज तक मूल पद पर वापसी नहीं हुई। सूत्रों के अनुसार संविलियन प्रक्रिया में समिति के समक्ष भ्रामक आंकड़े प्रस्तुत किए गए। साथ ही निकाय गठन के बाद कथित रूप से प्रस्तावों व दस्तावेजों में हेरफेर कर कुछ रिश्तेदारों/फर्मों को लाभ पहुंचाने और लेखा-नियमों के उल्लंघन के आरोप भी लगाए गए हैं। पंचायत राज संचालनालय के 28.06.2017 के पत्र का हवाला देते हुए कहा गया है कि ग्राम पंचायत सचिव का शहरी निकाय में संविलियन संभव नहीं है, फिर भी डूमरकछार में ऐसा किया गया। जनप्रतिनिधियों का कहना है कि न्यायालय के आदेशों की गलत व्याख्या कर कार्रवाई टाली जा रही है। उन्होंने विभागीय, अग्रिम व दंडात्मक कार्रवाई के लिए निष्पक्ष जांच की मांग दोहराई है। मामले में आधिकारिक प्रतिक्रिया की प्रतीक्ष है

धूल धक्कड़ से खिलाड़ी मुक्त, मोहन सरकार ने मिनी ब्राजील में फुटबॉल स्टेडियम के लिए खोला खजाना

शहडोल के मिनी ब्राजील विचारपुर गांव में बनेगा फुटबॉल स्टेडियम, मिलेंगी कई सुविधाएं, 5 करोड़ 10 लाख रुपए की स्वीकृति.

विचारपुर /शहडोल।

शहडोल- शहडोल जिले के मिनी ब्राजील को एक बार फिर से नई सौगात मिली है. जिले का विचारपुर गांव जिसे मिनी ब्राजील के नाम से जाना जाता है, वहां एक सर्व सुविधायुक्त फुटबॉल स्टेडियम बनने जा रहा है. इसके लिए मध्य प्रदेश शासन ने वित्तीय राशि भी स्वीकृत कर दी है.

मिनी ब्राजील को मिली सौगात

शहडोल जिले के विचारपुर गांव की पहचान मिनी ब्राजील के नाम से होने लगी है और अब इस गांव को एक नई सौगात मिलने जा रहा है, क्योंकि शहडोल जिले के विचारपुर गांव में खेलो इंडिया स्माल फुटबॉल सेंटर के लिए फुटबॉल ग्राउंड, बाउंड्री वॉल, चेंजिंग रूम, ऑफिशल रूम एवं पवेलियन निर्माण के लिए मध्य प्रदेश शासन की ओर से 5 करोड़ 10 लाख रुपए की राशि स्वीकृत कर

दी गई है. शहडोल जिले विचारपुर गांव में बनेगा फुटबॉल स्टेडियम खिलाड़ियों में खुशी की लहर फुटबॉल स्टेडियम के लिए राशि स्वीकृत हो जाने की खबर सुनते ही विचारपुर गांव के खिलाड़ियों में खुशी की लहर है. विचारपुर के फुटबॉल कोच अनिल सिंह कहते हैं कि ÷ये इस गांव और यहां के खिलाड़ियों के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, स्टेडियम बन जाने से यहां के फुटबॉल को पंख लग जाएंगे और यहां के खिलाड़ी बड़े लेवल पर बड़ा कमाल कर सकेंगे.÷

इसके अलावा पूर्व खिलाड़ी और कोच सीताराम सहीस, कोच यशोदा सिंह सभी का कहना है कि ÷जो खिलाड़ी अभी धूल भरे मैदान में फुटबॉल खेलने को मजबूर थे, अब उन्हें सर्व सुविधायुक्त फुटबॉल ग्राउंड मिलेगा. स्टेडियम मिलेगा और सुविधा मिलेगी तो यह नन्हे खिलाड़ी फुटबॉल में और बड़ा कमाल करेंगे, साथ ही विचारपुर गांव को भी एक नई पहचान मिलेगी ऊबड़-खाबड़ धूल भरे मैदान में फुटबॉल का जोश हाई, विदेशी कोच मिनी ब्राजील से निकालेंके इक्के फुटबॉल की नई सनसनी राधिनी सिंह, जर्मनी और कंबोडिया के कोच भी हुए कायल इस गांव की फुटबॉल से है पहचान शहडोल जिला मुख्यालय से लगा हुआ है विचारपुर गांव और इस गांव की पहचान मिनी ब्राजील के तौर पर होती है, क्योंकि इस गांव में हर दूसरे घर में आपको फुटबॉल के नेशनल खिलाड़ी मिल जाएंगे. लड़के लड़कियां सभी यहां फुटबॉल खेलते हैं. यहां कई ऐसे लड़के लड़कियां फुटबॉल प्लेयर हैं, जो 10-12 से भी ज्यादा नेशनल खेल चुके हैं इतना ही नहीं यहां 3 से 4 साल के बच्चे भी फुटबॉल खेलते नजर आते हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी इस गांव के फुटबॉल खिलाड़ियों के फुटबॉल प्रेम को देखकर प्रभावित हुए और मन की बात में कई बार इस गांव की चर्चा कर चुके हैं. वो मिनी ब्राजील के नाम से इस गांव को संबोधित भी कर चुके हैं. जर्मनी के फुटबॉल कोच, कंबोडिया के फुटबॉल कोच भी मिनी ब्राजील विचारपुर में यहां के खिलाड़ियों से मिलने आ चुके हैं. यहां के कुछ खिलाड़ी तो जर्मनी तक भी जा चुके हैं.

शासकीय विधि महाविद्यालय नर्मदापुरम के रासेयो के विशेष आवासीय शिविर में विविध गतिविधियां आयोजित

प्रथम दिवस पर विभागाध्यक्ष शिवाकांत मौर्य ने शिविर दल को हरी झंडी दिखाकर ग्राम पलासी के लिए रवाना किया। शिविर स्थल पर पहुंचने के बाद स्वयंसेवकों द्वारा विद्यालय परिसर में श्रमदान किया गया तथा स्वच्छता अभियान चलाकर परिसर को साफ-सुथरा बनाया गया। द्वितीय दिवस पर नशामुक्ति अभियान के अंतर्गत जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया तथा शिविरार्थियों एवं विद्यालय के विद्यार्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया। इस अवसर पर जिला चिकित्सालय से डॉ. अंशुल चौरे एवं नीलेश राठौर का विशेष सहयोग प्राप्त हुआ। इसी दिन फ़नशामुक्ति एवं मानसिक स्वास्थ्यफ़ विषय पर एक बौद्धिक सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता डॉ. तरुण रावत ने मानसिक स्वास्थ्य के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वर्तमान जीवनशैली में तनाव और नशे की प्रवृत्ति युवाओं के लिए गंभीर चुनौती बनती जा रही है। उन्होंने सकारात्मक सोच, नियमित दिनचर्या और संवाद को मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक बताया।तृतीय दिवस की शुरुआत स्वयंसेवकों द्वारा ग्राम में प्रभात फेरी निकालकर की गई, जिसमें स्वच्छता, नशामुक्ति और यातायात नियमों के पालन से संबंधित जागरूकता के नारे लगाए गए। इसके पश्चात योग एवं पीटी का आयोजन किया गया। परियोजना कार्य के अंतर्गत स्वयंसेवकों ने ग्रामीणों को यातायात जागरूकता विषय पर आयोजित बौद्धिक सत्र में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। आयोजित सत्र में मुख्य वक्ता के रूप में डॉ. प्रिंस जैन, प्राचार्य पंडित रामलाल शर्मा स्मृति महाविद्यालय उपस्थित रहे। उन्होंने अपने उद्बोधन में हेलमेट एवं सीट बेल्ट के उपयोग, वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग न करने तथा यातायात के पालन की आवश्यकता पर जोर दिया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में कपिल गौर, सरपंच ग्राम पंचायत उंदराखेड़ी उपस्थित रहे। शिविर के चतुर्थ दिवस पर ग्राम में विविध जागरूकता एवं सामाजिक गतिविधियाँ आयोजित की गईं। शिविर महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. कल्पना भारद्वाज के मार्गदर्शन एवं कार्यक्रम अधिकारी डॉ. महेन्द्र कुमार पटेल के निर्देशन में संचालित हो रहा है। चतुर्थ दिवस की शुरुआत विधिक साक्षरता रैली से हुई, जिसे मुख्य अतिथि न्यायाधीश विजय पाठक एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी अभय सिंह तथा प्राचार्य डॉ. कल्पना भारद्वाज ने हरी

झंडी दिखाकर रवाना किया। स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि ने। अपने संबोधन में कहा कि विधिक साक्षरता समाज को न्याय के प्रति जागरूक बनाती है। आप सभी स्वयंसेवक अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी जन-जन तक पहुँचाकर न्यायपूर्ण समाज के निर्माता बनें, तथा यह भी कहा कि विधिक सेवा से संबंधित कानून को विधि पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए जिससे विद्यार्थी में व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त हो। इस अवसर पर विशेष अतिथि डा सारिका मिश्रा प्राध्यापक शासकीय हमीदिया महाविद्यालय भोपाल, डा तरुण रावत शासकीय महाविद्यालय बुधनी की गरिमामय उपस्थित रहे। साथ ही विधिक सेवा प्रकोष्ठ के संयोजक डॉ. अभिषेक सिंह, राजदीप भदोरिया, डा ओम् शर्मा, डा हरिप्रकाश मिश्रा, भी उपस्थित रहे। रैली के माध्यम से स्वयंसेवकों ने ग्रामवासियों को उनके विधिक अधिकारों, नि:शुल्क विधिक सहायता तथा विभिन्न कानूनों के प्रति जागरूक किया। रैली के पश्चात स्वयंसेवकों द्वारा ग्राम में घर-घर सर्वेक्षण किया गया, जिसमें ग्रामीणों की विभिन्न विधिक समस्याओं को नोट किया गया। स्वयंसेवकों ने ग्रामीणों को उनकी समस्याओं के समाधान हेतु महाविद्यालय के विधिक सहायता क्लिनिक में आने के लिए आमंत्रित किया, ताकि उन्हें उचित मार्गदर्शन और सहायता प्रदान की जा सके। इसके पश्चात खेलकूद गतिविधियों के अंतर्गत स्वयंसेवकों ने प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थियों के साथ पारंपरिक राम-रावण खेल आयोजित किया, जिसमें बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत स्वयंसेवकों द्वारा अमृत वचन प्रस्तुत किए गए तथा रामलीला के संवादों का भावपूर्ण मंचन किया गया, जिससे ग्रामवासियों को भारतीय संस्कृति और नैतिक मूल्यों का संदेश मिला। स्वास्थ्य जागरूकता गतिविधि के अंतर्गत जिला चिकित्सालय से आए डॉ. अंशुल चौरे एवं उनके सहयोगियों ने शिविर स्थल पर उपस्थित रहकर ग्रामीणों एवं विद्यार्थियों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दी तथा ओआरएस के पैकेट वितरित किए। शिविर के पंचम दिवस की शुरुआत प्रभात फेरी से हुई तत्पश्चात योग के अंतर्गत सूर्य-नमस्कार किया गया । तथा परियोजना कार्य में स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत ग्राम एवं परिसर में साफ सफाई का कार्य रहा जिसमें स्वयंसेवकों ने स्वच्छता का संदेश दिया। कार्यक्रम में ग्रामवासी, विद्यार्थी एवं स्वयंसेवकों की सक्रिय सहभागिता रही। शिविर के माध्यम से ग्रामीणों में विधिक, स्वास्थ्य एवं सामाजिक जागरूकता का प्रभावी संदेश प्रसारित किया जा रहा है।

सहारा हॉस्पिटल सोफिया कॉलेज कैंपस महलगांव सिटी सेंटर ग्वालियर द्वारा रामगढ़ वार्ड क्रमांक 16 डबरा में निशुल्क नेत्र एवं स्वास्थ्य परीक्षण परामर्शवर आज - महाराज सिंह राजोरिया

डबरा।

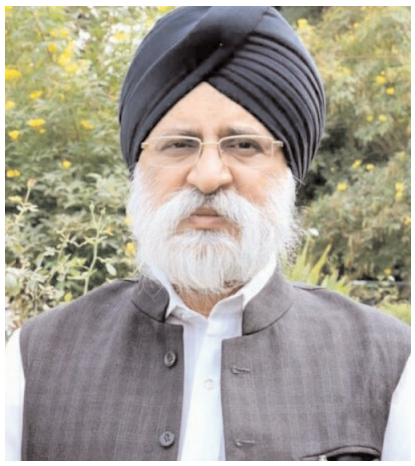

ग्वालियर चंबल अंचल का सर्वोत्तम हॉस्पिटल महलगांव सोफिया कॉलेज कैंपस सिटी सेंटर ग्वालियर के संचालक सुप्रसिद्ध वरिष्ठ चिकित्सक डॉ ए एस भल्ला नाक कान गला रोग विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में रामगढ़ वार्ड क्रमांक 16 डबरा में महाराज सिंह राजोरिया के निवास पुराना गाड़ी अड्डा रोड रामगढ़ डबरा में ने नि-शुल्क नेत्र एवं स्वास्थ्य परीक्षण परामर्श शिविर आज सुबह 10-00 से दोपहर 2-00 तक लगाया जा रहा है जिसमें मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण कर निशुल्क दवा वितरण की जाएगी तथा जो मरीज अपना पंजीयन कराएंगे जिनकी आंखों में मोतीयाविंद है तथा अन्य बीमारी से गंभीर पीड़ित है ऐसे लोगों का भी पंजीयन किया जाएगा और उनका सारा हॉस्पिटल की गाड़ी में ने सहारा हॉस्पिटल लाया जाएगा जहां पर उनकी प्रकार की जांच की जाएंगे और अस्पताल में भर्ती किए जाएंगे अस्पताल में आयुशमान योजना अंतर्गत निशुल्क इलाज किया जाएगा अस्पताल में डॉक्टर भल्ला की ओर से मरीजों तथा अटेंडर के लिए तथा बाहर से आने वाले मरीजों के लिए लंगर के माध्यम से निशुल्क भोजन की व्यवस्था भी है अस्पताल में 24 घंटे सेवाएं उपलब्ध हैं इमरजेंसी सेवाएं हैं एमएलसी सुविधा उपलब्ध है स्वास्थ्य बीमा धारकों के लिए कैशलेस इलाज की व्यवस्था है एक ही छत के नीचे सभी प्रकार की जांच की जाती हैं सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज किया जाता है ज्ञात रहे की हॉस्पिटल 35 साल से ग्वालियर अंचल में अपनी सेवा दे रहा है यह हॉस्पिटल पूर्व में बसंत विहार ग्वालियर में संचालित था जो अब महलगांव सोफिया कॉलेज कैंपस सिटी सेंटर में आ गया है डबरा क्षेत्र की जनता से तथा डबरा शहर की जनता से अपील है कि आज लगने वाले शिविर में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होने की अपील महाराज सिंह राजोरिया पूर्व चेयरमेंन नगर पालिका परिषद डबरा द्वारा की गई है

रायसेन जिले का गौरव- ग्राम पंचायत चीकली से सरपंच देवेंद्र पटेल के भतीजे कृष्णकांत पटेल ने रचा इतिहास

हल्केवीर सूर्यवंशी संभागीय संवाददाता

ग्राम पंचायत चीकली (जिला रायसेन) के होनहार युवा कृष्णकांत पटेल (पिता ङ्क श्री शिवप्रसाद पटेल) ने कठिन परिश्रम और दृढ़ संकल्प से चार-चार प्रतिष्ठित परीक्षाएँ उत्तीर्ण कर क्षेत्र का नाम रोशन कर दिया है। कृष्णकांत पटेल, जो कि ग्राम पंचायत चीकली के सरपंच देवेंद्र पटेल के भतीजे हैं, ने निम्न विभागों की परीक्षाओं में सफलता प्राप्त की है -

मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड – Assistant Engineer (AE)

मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड – Junior Engineer (JE)

Railway Recruitment Board –

Junior Engineer (JE)

मध्य प्रदेश खनिज संपदा विभाग – Sub Engineer

कृष्णकांत पटेल लगभग 6 वर्षों से लगातार तैयारी कर रहे थे। किसान परिवार से आने वाले कृष्णकांत ने सीमित संसाधनों के बावजूद स्वयं के दम पर पढ़ाई की और अपने लक्ष्य को हासिल किया। उनका पूरा डॉक्यूमेंटेशन भी पूर्ण हो चुका है और वे विशेष रूप से AE पद पर नियुक्ति लेना चाहते हैं। उनकी इस शानदार उपलब्धि से न केवल ग्राम पंचायत चीकली, बल्कि पूरे रायसेन जिले में खुशी की लहर है। परिवारजनों, गुरुजनों, मित्रों और ग्रामीणों ने उन्हें ढेरों शुभकामनाएँ और आशीर्वाद दिया है। कृष्णकांत पटेल की सफलता यह साबित करती है कि मेहनत, लगन और धैर्य से हर सपना साकार किया जा सकता है। उनका यह सफर युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है।

अमरकंटक में महिला की हत्या का 48 घंटे में खुलासा, भांजे ने गला दबाकर की थी वारदात

अमरकंटक/ अनूपपुर।

अमरकंटक/अनूपपुर। थाना अमरकंटक क्षेत्र में 65 वर्षीय महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने 48 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर सनसनीखेज खुलासा किया है। 23 फरवरी 2026 को सुदर्शन सिंह मरावी निवासी ग्राम दुवारी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी बहू गोमती बाई घर में मृत अवस्था में पाई गई हैं। घटनास्थल पर देशी शराब की बोतल, स्टील के बर्तन और अन्य सामग्री मिलने से हत्या की आशंका जताई गई थी। मृतका के गले और चेहरे पर चोट के निशान पाए गए पुलिस ने अपराध क्रमांक 33/26 धारा 103(1) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। विवेचना के दौरान मोबाइल कॉल डिटेल्स

और सायबर सेल की मदद से संदेह मृतका के मूक-बोले भांजे बुढ़राम सिंह पिता गोरे सिंह गोंड (33) निवासी ग्राम महोरा, थाना राजेन्द्रग्राम पर गया। पूछताछ में आरोपी ने मृतका से प्रेम प्रसंग और घटना दिवस घर जाने की बात स्वीकार करते हुए गला दबाकर हत्या करना कबूला उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी अमरकंटक लाल बहादुर तिवारी के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। टीम में यू.पी.एस. बैचेल, ईश्वर यादव, धनंजय, पून सिंह मरावी, प्रवीण कुमरे, कृष्णा सिंह राजावत, रवि पटेल, ऋषभ सिंह और पवन तिवारी शामिल रहे। आरोपी को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है

मानवाधिकार आयोग की फटकार के बाद जागा जिला प्रशासन

भोपाल। राजधानी भोपाल के 10 नंबर मार्केट अरेरा कॉलोनी में नियम विरुद्ध संचालित हो रही अवैध शराब दुकान मामले में जिला प्रशासन एकबार फिर हरकत में आया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियांक कानूनगो द्वारा किए गए निरीक्षण एवं कड़ी फटकार के बाद जिला प्रशासन,आबकारी विभाग समेत कई विभागों के अधिकारी जांच करने पहुंचे। इस दौरान रहवासियों और प्रशासनिक अमले के बीच हॉट टॉक भी हुई। मानवाधिकार आयोग द्वारा मामले का संज्ञान लेने के बाद जिला कलेक्टर ने एडीएम पी सी शाक्य की अध्यक्षता में चार सदस्यीय जांच दल गठित किया है, जिसमे आबकारी अधिकारी वीरेंद्र धाकड़, विधि अधिकारी राजेंद्र उपाध्याय,पटवारी,आर आई नगर निगम के अधिकारी,राजस्व विभाग के अधिकारी, कर्मचारी मौजूद रहे। टीम गुरुवार को अरेरा कॉलोनी स्थित शराब दुकान की वैधानिकता की जांच करने? पहुची। जांच के दौरान, शिकायतकर्ता, स्थानीय रहवासी एवं आर्य समाज मंदिर के व्यवस्थापक अपने-अपने दस्तावेज़ एवं साक्ष्यों के साथ उपस्थित रहें एवं शराब दुकान संचालक और जिला प्रशासन के खिलाफ नाराजगी ज़ाहिर की। फर्जी जांच रिपोर्ट से गुमराह करने का आरोप स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि इससे पूर्व आबकारी विभाग के कुछ अधिकारियों द्वारा फर्जी जांच रिपोर्ट तैयार कर भोपाल कलेक्टर,राज्य सरकार एवं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को गुमराह किया गया था। पूर्व की जांच में प्रशासन द्वारा आर्य समाज मंदिर को मंदिर मानने से ही इंकार कर दिया गया था, जो धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला और तथ्यात्मक रूप से संदिग्ध कदम था। रिपोर्ट में कई भ्रामक असत्य एव अधूरी जानकारियाँ दी गई जिससे सीधा लाभ शराब माफिया को मिले। रहवासियों ने मांग की दुकान संचालक पर प्रकरण दर्ज कर जुर्माना लगाया जाए और निरस्त हो लाइसेंस स्थानीय रहवासी विवेक त्रिपाठी ने मांग की है कि अरेरा कॉलोनी में नियम विरुद्ध संचालित शराब दुकान संचालक पर आर्थिक दंड लगाया जाए, संबंधित दुकान एवं उससे जुड़ी अन्य दुकानों के लाइसेंस नवीनीकरण के समय प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच कराई जाए और जांच में दोषी पाए जाने पर लाइसेंस निरस्तो की कार्यवाही की जाए। साथ ही स्थानीय रहवासियों के कथन एवं उनकी शिकायतों को विधिवत दर्ज कर जांच का हिस्सा बनाया जाए।

आधुनिक युग में युवाओं को सलाह: अतर सिंह भारतीय

आलेख अतर सिंह भारतीय
(सामाजिक कार्यकर्ता, भोपाल म. प्र.)

1. अपनी यौन इच्छाओं पर नियंत्रण ही आपकी सफलता या असफलता का कारण होगा। 2. पोर्न और हस्तमैथुन सफलता का सबसे बड़ा हत्यारा है। यह आपके मस्तिष्क को अवरुद्ध और नष्ट कर देता है। 3. ऊँट की तरह शराब पीने से बचें। अपने होश खोने और मूर्ख बनने से बुरा कुछ नहीं है। 4. अपने मानक ऊँचे रखें और किसी चीज़ से सिर्फ़ इसलिए संतुष्ट न हों कि वह उपलब्ध है। 5. अगर आपको कोई आपसे ज़्यादा होशियार मिले, तो उसके साथ काम करें, प्रतिस्पर्धा न करें। 6. कोई भी आपकी समस्याओं को बचाने नहीं आ रहा है। आपके जीवन की शतप्रतिशत ज़िम्मेदारी आपकी ही है। 7. आपको ऐसे लोगों से सलाह नहीं लेनी चाहिए जो जीवन में उस मुकाम पर नहीं हैं जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं। 8. पैसे कमाने के नए तरीके खोजें। पैसे कमाएँ और उन मज़ाक करने वालों को नज़रअंदाज़ करें जो आपका मज़ाक उड़ाते हैं। 9. आपको 100 सेल्फ़-हेल्प किताबों की ज़रूरत नहीं है, आपको बस कार्रवाई और आत्म-अनुशासन की ज़रूरत है। अनुशासित रहें! 10. नशीली दवाओं से बचें। खरपतवार से बचें। 11. YouTube पर कौशल सीखें, नेटफ्लिक्स पर घटिया सामग्री देखने में अपना समय बर्बाद न करें। 12. कोई भी आपकी परवाह नहीं करता। इसलिए शर्मीलेपन को छोड़ें, बाहर जाएँ और अपने लिए अवसर बनाएँ। 13. आराम सबसे बुरी लत है और अवसाद का सस्ता टिकट है। 14. अपने परिवार को प्राथमिकता दें। भले ही वे बदबूदार हों, भले ही वे मूर्ख हों, उनका बचाव करें। उनकी मजबूरी , भेद को छिपाएँ। काम में सहयोगी बने न कि रोड़ा। 15. नए अवसर खोजें और अपने से आगे के लोगों से सीखें। 16. किसी पर अत्यधिक भरोसा न करें। किसी एक पर भी नहीं, चाहे आपको कितना भी प्रलोभन क्यों न दिया जाए। खुद पर विश्वास रखें। 17. चमत्कार होने का इंतज़ार न करें। हाँ, आप हमेशा अकेले नहीं कर सकते, लेकिन लोगों की राय न सुनें। 18. कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प आपको कुछ भी हासिल करा सकता है। खुद को विनम्र बनाना ही आपको ऊँचा उठाता है। 19. खुद को खोजने का इंतज़ार करना बंद करें। इसके बजाय खुद को बनाएँ। 20. दुनिया आपके लिए धीमी नहीं होगी। 21. कोई भी आपका कुछ भी कर्जदार नहीं है। 22. जीवन एक एकल खिलाड़ी का खेल है। आप अकेले पैदा हुए हैं। आप अकेले मरने वाले हैं। आपकी सभी व्याख्याएँ अकेली ही हैं। आप तीन पीढ़ियों में चले गए हैं और किसी को परवाह नहीं है। आपके आने से पहले, किसी को परवाह नहीं थी। यह सब एकल खिलाड़ी है। 23. आपका जीवन पथ इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि आप हर समय ज़रूरतमंद, उदास और कमज़ोर महसूस करते हैं। और केवल एक ही रास्ता है, जो बाहर निकलने का फैसला करना है। आपके अलावा कोई भी खुद को और अपने प्रियजनों को नहीं बचा सकता। 24. हर किसी का दिल आपके जैसा नहीं होता। हर कोई आपके साथ उतना ईमानदार नहीं होता जितना आप उनके साथ हैं। आप ऐसे लोगों से मिलेंगे जो आपको अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करेंगे और फिर अपने जीवन का वह हिस्सा बीत जाने और संतुष्ट होने के बाद आपको त्याग देंगे। इसलिए सजग, निडर होकर जागते रहें। 25. आपको 25 वर्ष की आयु तक इतना समझदार हो जाना चाहिए कि दूसरों की सफलता का जश्न मनाएँ, ईर्ष्या और जलन से बचें। अपना दिमाग खुला रखें। हरेक बात पर अनुमान लगाने से बचें। इरादा मजबूत रखें और सूझबूझ से काम करें। कृतज्ञता का अभ्यास करें। ईमानदारी से स्पष्ट बोलें। हो सके तो रोज़ाना व्यायाम करें। गपशप से बचें। स्वच्छ भोजन करें। जरूरत पड़ने पर लोगों को माफ करें। जरूरी बात को गौर से सुनें। सीखने में कंजूसी कतई न करें शीघ्रता से सीखें। प्रकृति से प्यार करें।

इटारसी: डेढ़ लाख की सोने की खोई हुई अंगूठी लौटाकर कृष्णा चौधरी ने ईमानदारी की मिसाल पेश की

हल्केवीर सूर्यवंशी संभागीय संवाददाता

इटारसी। ईमानदारी का एक अनोखा उदाहरण देखने को मिला, जब कांग्रेस के युवा नेता और समाजसेवी ने एक सोने की बेशकीमती अंगूठी को उसके सही मालिक तक पहुंचाया।

कृष्णा ने बताया कि आज कांग्रेस के एक प्रदर्शन कार्यक्रम के दौरान उनकी नजर एक बेशकीमती सोने की अंगूठी पर पड़ी,जिसे उन्होंने उठाकर सुरक्षित अपने जेब में रखा। कुछ देर बाद अंगूठी मालिक रामशंकर सोनकर (जिला अध्यक्ष, खेल खिलाड़ी प्रकोष्ठ,नर्मदापुरम) को सही सलामत सौंपा। अंगूठी मालिक ने कृष्णा का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष गुड्डन पांडे जी, इटारसी नगर अध्यक्ष कन्हैया गोस्वामी जी, जिला अध्यक्ष, अनुसूचित जाति विभाग इंजीनियर अजय अहिरवाल जी सहित वरिष्ठ नेताओं ने कृष्णा की सराहना की।

उदयपुरा तहसील में आगजनी, फायर ब्रिगेड डेढ़ घंटे देरी से पहुंची लापरवाही पर उठे सवाल

हल्केवीर सूर्यवंशी संभागीय संवाददाता

उदयपुरा/रायसेन। दिनांक 21 फरवरी 2026 की रात लगभग 11 बजे तहसील उदयपुरा अंतर्गत ग्राम किरगी खुर्द और किरगी मोड़ में आगजनी की घटना सामने आई। जानकारी के अनुसार मानसिंह/मलखान सिंह राजपूत निवासी ग्राम किरगी खुर्द एवं जुझार सिंह/पन्नालाल राजपूत निवासी वार्ड क्रमांक 05 किरगी मोड़ के यहां अचानक आग लग गई। घटना की सूचना मिलते ही 100 डायल पुलिस मौके पर पहुंच गई, लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ी करीब डेढ़ घंटे की देरी से पहुंची। बताया जा रहा है कि 100 डायल कर्मियों और थाना प्रभारी काकौड़ियां द्वारा फायर ब्रिगेड ऑपरेटर को कई बार फोन लगाए गए, मगर फोन रिसीव नहीं किया गया। अंततः ग्राम किरगी खुर्द के सरपंच हेमराज सिंह चौहान द्वारा लगातार संपर्क करने के बाद फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। हालांकि, फायर ब्रिगेड की देरी से पहुंचने के कारण काफी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। स्थानीय लोगों में फायर ब्रिगेड ऑपरेटर की कथित लापरवाही को लेकर आक्रोश है और जिम्मेदारी तय करने की मांग उठ रही है।

सूचना मिलने पर मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल के सुपुत्र अभिज्ञान पटेल भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने प्रभावित परिवारों को उचित मुआवजा दिलवाने का आश्वासन दिया।

खाद्य सुरक्षा टीम द्वारा विभिन्न प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया

भोपाल।

होली के त्योहार को ध्यान में रखते हुए एवं आमजन को शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने तथा स्वच्छ परिस्थितियों में खाद्य सामग्री का निर्माण, विक्रय एवं संग्रहण सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से कार्यलय आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं कलेक्टर भोपाल के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की संयुक्त टीम द्वारा मंगलवारा स्थित फर्म अमित नमकीन सेंटर, रेल्वे स्टेशन पावर हाउस रोड भोपाल स्थित फर्म साहू मावा भण्डार, रेल्वे स्टेशन भोपाल क्षेत्र में स्थित फर्म शारदा स्वाद संसार मिष्ठन भण्डार, कटारा हिल्स भोपाल स्थित फर्म परमार डेरी एवं समर्थ डेरी, बंगरासिया भोपाल स्थित, 80 फिट रोड करोंद भोपाल स्थित फर्म महादेव ग्राइंडिंग एवं न्यू भारत टी एण्ड किराना,फर्म भोज कैफे आदि फर्मों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान सभी निर्माताओं, विक्रेताओं को स्वच्छ परिस्थितियों में गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ नमकीन, मिठाई, मावा आदि निर्माण/विक्रय किये जाने के निर्देश टीम ने दिये। अमित नमकीन सेंटर से मिलक केक एवं राकेश प्रीमियम स्नैक्ड, महादेव ग्राइंडिंग से लाल मिर्च पवाडर, न्यू भारत टी एण्ड किराना से सरसों का तेल, साहू मावा भण्डार से मावा एवं घी, शारदा स्वाद संसार मिष्ठान भण्डार बर्फी एवं खुरमे, परमार डेरी से दूध, समर्थ डेरी से टोस्ट एवं पनीर, भोज कैफे से छोला, भटूरे, तेल, मैदा के नमूने जॉच हेतु लिये गये।

सभी नमूने राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल प्रेषित किये गये हैं। जांच परिणामों के आधार पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम,2006 के अन्तर्गत विधि अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

करोड़ों का प्रावधान, लेकिन ज़मीन पर इंतज़ारः यह कैसा शैक्षणिक न्याय?

कभी-कभी अन्याय शोर नहीं करताज्वह चुपचाप भविष्य की दिशा बदल देता है। विद्यायालीन तथा स्नातक-स्नातकोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति और जनजाति के वे विद्यार्थी जो अपने परिवार की उम्मीदों का एकमात्र सहारा हैं जब वर्ष भर बिना पर्याप्त स्टेशनरी, बिना समय पर किताबों के कक्षा में बैठते हैंज्तो वे केवल नोट्स नहीं खोते, वे प्रतिस्पर्धा में अपना आत्मविश्वास भी खोने लगते हैं। एक ओर विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम आगे बढ़ता रहता है..प्रोजेक्ट, असाइनमेंट और परीक्षाएँ समय पर चलती रहती हैं वहीं दूसरी ओर छात्रावास के छोटे कमरों में कुछ विद्यार्थी उधार की कॉपियों पर लिखते हैं, पुरानी किताबों से तैयारी करते हैं या मित्रों की नोटबुक पर निर्भर रहते हैं। जब उन्हें किताबें और स्टेशनरी परीक्षा के बाद मिलती हैं...तो यह केवल सामग्री का विलंब नहीं होता, यह अवसरों की समानता पर सीधा आघात होता है। मध्यप्रदेश के शासकीय छात्रावासों में निवास करते अनुसूचित आदिवासी पिछड़े वर्ग के हजारों छात्र-छात्राओं की यह व्यथा केवल प्रशासनिक चूक नहीं,बल्कि सामाजिक न्याय की कसौटी पर एक गंभीर प्रश्न है। और तब हृदय में यकायक ही एक प्रश्न उठता है...यदि संसाधन समय पर न मिलें, तो शिक्षा का अधिकार आखिर किसके लिए रह जाता है?? जब किताबें परीक्षा के बाद अथवा वर्ष के अंत में मिलें तो फिर इनका क्या औचित्य? यह प्रश्न आज मध्यप्रदेश की शैक्षणिक व्यवस्था के सामने एक गंभीर और असहज सच बनकर खड़ा है। एक ओर बजट भाषणों में विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की प्रतिबद्धता दोहराई जाती है, सैकड़ों करोड़ रुपये के प्रावधान घोषित किए

कु.प्रियंका जाटव
[लेखिकाः सामाजिक कार्यकर्ता विचारक-चिंतक]

जाते हैं; दूसरी ओर जमीनी स्तर पर अनेक विद्यार्थी पूरे शैक्षणिक सत्र मेंआवश्यक पुस्तकें, स्टेशनरी और यहां तक कि स्वीकृत छात्रवृत्ति के बिना संघर्ष करते दिखाई देते हैं। मध्यप्रदेश में अनुसूचित जाति-जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लाखों विद्यार्थी ऐसे परिवारों से हैं जिनके लिए पाठ्यपुस्तक, कॉपी और लेखन सामग्री खरीदना भी आर्थिक चुनौती है। इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण, स्टेशनरी सहायता, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति और मेधावी विद्यार्थियों के लिए विशेष योजनाएँ संचालित की जाती हैं। वर्ष 2026-27 के बजट में मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के अंतर्गत लगभग ?750 करोड़ तथा पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए लगभग ?766 करोड़ का प्रावधान घोषित किया गया है। यह राशि दर्शाती है कि शिक्षा और छात्र हितों के लिए संसाधनों की घोषणा में कमी नहीं है। किन्तु प्रश्न केवल बजट का नहीं, उसके प्रभावी क्रियान्वयन का है। प्रदेश के अनेक जिलों से लगातार शिकायतें आती रही हैं कि विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तकें सत्र के अंतिम चरण में, परीक्षा से ठीक पहले या परीक्षा समाप्त होने के बाद वितरित की जाती हैं। जब पूरा वर्ष बीत चुका हो, तब पुस्तकों का औचित्य क्या रह जाता है? शिक्षा का अधिकार केवल विद्यालय में नामांकन तक सीमित नहीं है; यह समय पर संसाधनों की उपलब्धता की भी गारंटी मांगता है। यदि संसाधन ही विलंब से मिलें तो समान अवसर की अवधारणा कमजोर पड़ जाती है। स्थिति यहीं समाप्त नहीं होती। गंभीर चिंता का विषय यह भी है कि बड़ी संख्या में विद्यार्थियों की पिछले दो वर्षों की छात्रवृत्ति राशि लंबित बताई जा रही है। कई विद्यार्थियों को शैक्षणिक सत्र 2023-24 और 2024-25 की स्वीकृत छात्रवृत्ति अब तक पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हुई है। जिन परिवारों की मासिक आय सीमित है, उनके लिए छात्रवृत्ति केवल प्रोत्साहन नहीं, बल्कि फीस जमा करने, किराया देने, पुस्तकों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का आधार होती है। जब यह राशि समय पर न मिले, तो विद्यार्थी कर्ज लेने, पढ़ाई बीच में छोड़ने या मानसिक तनाव का सामना करने के लिए विवश हो जाते हैं। वितरित स्टेशनरी की गुणवत्ता को लेकर भी प्रश्न उठ रहे हैं। कमजोर बाइंडिंग वाली कॉपियाँ, निम्न स्तर का कागज और अल्पकालिक लेखन सामग्री यह संकेत देती है कि निगरानी और गुणवत्ता नियंत्रण पर्याप्त प्रभावी नहीं है। जब योजनाओं के लिए सैकड़ों करोड़ रुपये स्वीकृत हैं, तो गुणवत्ता से समझौता क्यों? यदि बजट पर्याप्त है तो पारदर्शिता और जवाबदेही भी उतनी ही मजबूत होनी चाहिए। यह विषय किसी एक विभाग की कार्यप्रणाली का नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय की मूल भावना का है। अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए बनाई गई योजनाएँ ऐतिहासिक वंचनाओं को संतुलित करने का माध्यम हैं। यदि किताबें देर से मिलें और छात्रवृत्ति वर्षों तक लंबित रहे, तो यह केवल प्रशासनिक त्रुटि नहीं, बल्कि अवसरों का असंतुलन है। समय की मांग है कि पाठ्यपुस्तक और स्टेशनरी का वितरण शैक्षणिक सत्र के प्रथम माह में अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए। छात्रवृत्ति भुगतान की स्थिति जिला-वार सार्वजनिक पोर्टल पर प्रदर्शित हो। लंबित छात्रवृत्तियों का विशेष अभियान चलाकर समयबद्ध निराकरण किया जाए। क्रय प्रक्रिया, गुणवत्ता परीक्षण और भुगतान प्रणाली को पूर्णतः पारदर्शी बनाया जाए तथा विलंब के लिए स्पष्ट जवाबदेही तय की जाए। शिक्षा पर किया गया व्यय खर्च नहीं, बल्कि भविष्य में निवेश है। वर्ष 2026ङ्क27 के बजट में घोषित सैकड़ों करोड़ रुपये तभी सार्थक होंगे जब वे समय पर विद्यार्थियों तक पहुँचें। जब किताबें सत्र की शुरुआत में मिलती हैं और छात्रवृत्ति समय पर खाते में आती है, तब वह राशि भविष्य गढ़ती है और जब वे परीक्षा के बाद या वर्षों की देरी से मिलती हैं, तब वे केवल आंकड़ों में दर्ज उपलब्धि बनकर रह जाती हैं। प्रश्न स्पष्ट है...क्या हम सचमुच समान अवसर सुनिश्चित करना चाहते हैं, या फिर योजनाओं को कागज़ी उपलब्धि तक सीमित रखना चाहते हैं? क्योंकि शिक्षा तथा शैक्षणिक संसाधनों में देरी केवल देरी नहीं होती बल्कि वह किसी विद्यार्थी के सपनों पर लगा विराम होती है।

सहारा हॉस्पिटल द्वारा निशुल्क नेत्र एवं स्वास्थ्य परीक्षण शिविर में 200 से अधिक लोगों ने लिया लाभ

ग्वालियर।

ग्वालियर-चंबल अंचल के सुप्रसिद्ध सहारा हॉस्पिटल, सोफिया कॉलेज कैंपस, महलगांव, सिटी सेंटर, ग्वालियर द्वारा डबरा के वार्ड क्रमांक 16, रामगढ़ क्षेत्र में एक विशाल निशुल्क नेत्र एवं स्वास्थ्य परीक्षण परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर

में 200 से अधिक लोगों ने नेत्र एवं सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण कराकर विशेषज्ञ परामर्श प्राप्त किया। यह शिविर दलित आदिवासी महापंचायत के कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष तथा डबरा नगर पालिका परिषद के पूर्व चेयरमैन श्री महाराज सिंह राजोरिया एवं वार्ड क्रमांक 16 की पार्षद श्रीमती सुनीता राजोरिया के विशेष प्रयासों से संपन्न हुआ।

सुप्रसिद्ध वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. एस. बाला (नाक, कान एवं गला रोग विशेषज्ञ) के मार्गदर्शन में आयोजित इस शिविर में नेत्र एवं मेडिसिन विशेषज्ञ चिकित्सकों तथा सहारा हॉस्पिटल की टीम द्वारा सुबह 10ः00 बजे से दोपहर 3ः00 बजे तक 200 से अधिक मरीजों का परीक्षण किया गया। शिविर के सफल संचालन में हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉ. जबर सिंह यज्ञ की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उनके कुशल नेतृत्व एवं विशेष सहयोग से संपूर्ण व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित रहीं। साथ ही अन्य चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ ने भी पूर्ण समर्पण भाव से अपनी सेवाएं प्रदान कीं।

यह शिविर महर्षि राजोरिया के पुराना गाड़ी अड्डा रोड स्थित निवास पर आयोजित किया गया, जिसमें डबरा शहर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में महिला एवं पुरुष अपनी जांच कराने पहुंचे। स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान नेत्र रोग, विशेषकर मोतियाबिंद के कई मरीज चिन्हित किए गए, जिनका मौके पर ही पंजीयन किया गया। पंजीकृत मरीजों को सहारा हॉस्पिटल की ओर से निशुल्क वाहन सुविधा उपलब्ध कराकर ग्वालियर लाया गया। शिविर में मेडिसिन से संबंधित लगभग 30 मरीजों का भी पंजीयन किया गया, जिनका उपचार आयुष्मान योजना के अंतर्गत सहारा हॉस्पिटल में निशुल्क किया जाएगा। साथ ही कुछ मरीजों की सर्जरी भी की जाएगी। शिविर के सफल आयोजन पर श्री महाराज सिंह राजोरिया एवं उनकी धर्मपत्नी पार्षद श्रीमती सुनीता राजोरिया ने कहा कि ÷मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है।÷ उन्होंने डॉ. जबर सिंह यज्ञ एवं उनकी पूरी टीम का तथा शिविर का लाभ उठाने वाले क्षेत्रवासियों का आभार व्यक्त किया। शिविर को सफल बनाने में मंगल सिंह राजोरिया, भगवान लाल कुशवाहा, गजेंद्र सिंह ठाकुर, दास देवेंद्र सिंह, लाल सिंह, दाताराम, प्रमोद आदि का विशेष योगदान रहा।

बस्तर जिले में गुटखा, सिगरेट एवं तंबाकू उत्पादों में जमाखोरी-मुनाफाखोरी का खेल

जगदलपुर। बस्तर जिले विशेषकर जगदलपुर शहर में इन दिनों गुटखा, सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पादों की कीमतों को लेकर भारी अव्यवस्था और कथित लूट की स्थिति बनी हुई है। लगातार शिकायतें मिल रही हैं कि थोक (Wholesale) व्यापार करने वाले कुछ कारोबारी जमाखोरी और मुनाफाखोरी कर रहे हैं तथा खुदरा (Retail) विक्रेताओं को ही पैकेट पर अंकित अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) से अधिक दर पर माल उपलब्ध करा रहे हैं। इसका सीधा प्रभाव आम उपभोक्ताओं पर पड़ रहा है। खुदरा व्यापारी भी मजबूरी में उपभोक्ताओं को एमआरपी से अधिक कीमत पर सामान बेचने को विवश हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें स्वयं बढ़ी हुई दर पर माल दिया जा रहा है। इस प्रकार पूरे सिस्टम में कृत्रिम मूल्य वृद्धि कर आम जनता की जेब पर सीधा बोझ डाला जा रहा है।

यह स्थिति अत्यंत गंभीर है क्योंकि यह केवल बाजार की सामान्य प्रक्रिया नहीं बल्कि सुनियोजित तरीके से मुनाफाखोरी का मामला प्रतीत होता है। यदि किसी उत्पाद पर एमआरपी अंकित है तो उससे अधिक कीमत वसूलना नियमों के विरुद्ध है, फिर भी खुलेआम यह सब चल रहा है। सबसे चिंताजनक तथ्य यह है कि गुटखा, सिगरेट एवं तंबाकू उत्पादों में यह कथित लूट लंबे समय से जारी है और थोक व्यापार करने वाले कुछ लोग खुलेआम जनता को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाकर अपनी तिजोरी भर रहे

हैं। इससे यह संदेह भी उत्पन्न होता है कि कहीं न कहीं बाजार व्यवस्था को प्रभावित करने के लिए जानबूझकर कृत्रिम कमी (Artificial Shortage) बनाई जा रही है।इस पूरे मामले में कई गंभीर प्रश्न खड़े होते हैं क्या संबंधित विभागों को इस स्थिति की जानकारी नहीं है? क्या औषधि एवं तंबाकू नियंत्रण से जुड़े जिम्मेदार अधिकारियों को यह सब दिखाई नहीं दे रहा?

क्या जिला प्रशासन को बाजार में चल रही इस अव्यवस्था का पता नहीं है?

या फिर किसी प्रकार की सांठगांठ के कारण कार्रवाई नहीं हो रही?

जनता के बीच यह चर्चा भी आम है कि यदि प्रशासन को जानकारी होने के बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही, तो यह स्थिति व्यवस्था पर अविश्वास पैदा करती है। प्रशासन का दायित्व है कि वह आम नागरिकों को शोषण से बचाए और बाजार में पारदर्शिता सुनिश्चित करे। शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) स्पष्ट रूप से यह कहना चाहती है कि हम खुदरा व्यापारियों को दोषी नहीं मानते, क्योंकि वे भी इस कथित थोक मुनाफाखोरी के शिकार हैं। वास्तविक जांच का दायरा थोक आपूर्ति श्रृंखला (Supply Chain) तक जाना चाहिए, जहां से मूल्य वृद्धि की शुरुआत हो रही है।

संगठन की मांगें निम्नलिखित हैं-

पूरे जिले में गुटखा, सिगरेट एवं तंबाकू उत्पादों के थोक व्यापारियों की विशेष जांच कराई जाए। जमाखोरी एवं कृत्रिम मूल्य वृद्धि करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। एमआरपी से अधिक कीमत पर बिक्री रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। खुदरा व्यापारियों को उचित दर पर माल उपलब्ध कराने हेतु निगरानी तंत्र विकसित किया जाए। उपभोक्ताओं के लिए शिकायत दर्ज करने की प्रभावी व्यवस्था बनाई जाए। यदि शीघ्र ही इस विषय में ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) जनता, व्यापारी वर्ग एवं सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर लोकतांत्रिक आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। जनता का आर्थिक शोषण किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। हम जिला प्रशासन से अपेक्षा करते हैं कि वह निष्पक्ष जांच कर सच्चाई जनता के सामने लाए और दोषियों पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करे, ताकि बाजार व्यवस्था में विश्वास बहाल हो सके।

केन-बेतवा लिंक परियोजना : विस्थापितों के अधिकारों को लेकर प्रतिनिधिमंडल नें की अखिलेश यादव से मुलाकात, पूर्ण समर्थन का आश्वासन

यह राजनीतिक नहीं, न्याय की लड़ाई है : अमित भटनागर

छतरपुर।

केन-बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित किसानों, आदिवासी परिवारों एवं ग्रामीणों के प्रतिनिधिमंडल ने आज दतिया में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव से व्यक्तिगत रूप से बैठकर विस्तृत चर्चा की तथा उन्हें तथ्यात्मक ज्ञापन और पत्र सौंपा। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सामाजिक कार्यकर्ता अमित भटनागर ने किया। प्रतिनिधिमंडल ने स्पष्ट किया कि यह मुलाकात किसी राजनीतिक उद्देश्य से नहीं, बल्कि हजारों विस्थापित किसानों, आदिवासियों और ग्रामीणों के संवैधानिक अधिकार, सम्मानजनक पुनर्वास और न्याय की मांग को लेकर की गई है।

अमित भटनागर ने रखा कानून उल्लंघन और घटनाक्रम का पूरा पक्ष

अमित भटनागर ने बताया कि केन-बेतवा परियोजना में भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन से जुड़े 2013 के कानून (LAR Act 2013) के प्रावधानों के पालन को लेकर गंभीर सवाल हैं। उन्होंने कहा कि प्रभावित परिवार लंबे समय से शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन कई बार प्रशासनिक कार्रवाई, गिरफ्तारी और दमन जैसी घटनाएं सामने आई। उन्होंने 9 फरवरी 2026 को अपनी गिरफ्तारी सहित पूरे घटनाक्रम, आंदोलन और ग्रामीणों की समस्याओं का विस्तृत विवरण रखा। आंदोलनकारियों पर दमन, मारपीट और फर्जी मुकदमों का मुद्दा उठाया प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि अपने हक और सम्मानजनक पुनर्वास की मांग को लेकर शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे ग्रामीणों, महिलाओं और युवाओं पर प्रशासनिक दमन की कई घटनाएँ सामने आई, जिनमें कथित रूप से प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार, लाठीचार्ज और मारपीट की गई तथा लोगों को कई किलोमीटर तक खदेड़ा गया। इस दौरान अनेक वाहनों को नुकसान पहुँचा और एक सैकड़ा से अधिक लोग घायल हुए। प्रतिनिधिमंडल ने आरोप लगाया कि आंदोलन से जुड़े कई लोगों पर फर्जी मुकदमे दर्ज कर धमकियाँ दी गई, जिससे क्षेत्र में भय और दहशत का माहौल बना। इस पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग अखिलेश यादव के समक्ष रखी गई।

ज्ञापन में प्रतिनिधिमंडल ने पूर्व मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि प्रभावित क्षेत्रों के लिए स्वतंत्र तथ्य-जांच अथवा प्रतिनिधिमंडल भेजने की पहल की जाए, संसद एवं राष्ट्रीय मंचों पर इस मुद्दे को प्राथमिकता से उठाया जाए, भूमि अधिग्रहण कानून के प्रावधानों के पालन की स्वतंत्र जांच कराई जाए तथा आंदोलनकारियों पर दर्ज मामलों और दमनात्मक कार्रवाइयों के विरुद्ध न्यायपूर्ण हस्तक्षेप किया जाए। साथ ही प्रभावित ग्रामीणों से प्रत्यक्ष संवाद हेतु क्षेत्र भ्रमण या प्रतिनिधिमंडल बैठक का समय देने का भी अनुरोध किया गया।

अखिलेश यादव ने जताया समर्थन

ग्रामीणों की पूरी बात सुनने के बाद श्री अखिलेश यादव ने कहा कि विकास के नाम पर गरीबों, किसानों और आदिवासियों के अधिकारों की अनदेखी स्वीकार नहीं की जा सकती। उन्होंने पारदर्शी सर्वे, कानून के पालन और प्रभावितों को न्याय दिलाने की मांग का समर्थन किया तथा मामले को गंभीरता से देखने का आश्वासन दिया।

प्रशासन से संवाद जारी, संघर्ष भी जारी

प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि वर्तमान में जनभावना को देखते हुए प्रशासन द्वारा सर्वे टीम गठित करने और पारदर्शी प्रक्रिया अपनाने का आश्वासन दिया गया है।

अमित भटनागर ने कहा कि आंदोलन किसी सरकार या व्यक्ति के विरोध का नहीं, बल्कि संविधानसम्मत न्याय, सम्मानजनक पुनर्वास और कानून के पालन का है। जब तक प्रत्येक प्रभावित परिवार को उसका अधिकार नहीं मिल जाता, लोकतांत्रिक एवं शांतिपूर्ण संघर्ष जारी रहेगा।

प्रतिनिधिमंडल में शामिल

प्रतिनिधिमंडल में अमित भटनागर, पार्षद दिव्या अहिरवार, पार्षद रामपाल शर्मा, राहुल अहिरवार, पवन पटेल, हिसाबी राजपूत, अनमोल आदिवासी, विनोद अहिरवार, दशरथ रैकवार, राजा आदिवासी, कल्लू यादव, ग्यासी रैकवार, विष्णू बंसल, भगवान दास पटेल, किशोरी आदिवासी, रोहित रैकवार, कमलेश यादव, भुन्नू अहिरवार, भागीरथ यादव, इमरतलाल अहिरवार, अशोक यादव सहित अनेक प्रभावित ग्रामीण शामिल रहे। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव, प्रदेश सचिव हुसैन निजामी, जिला अध्यक्ष कपूर सिंह सहित अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित रहे।

प्रदेश अध्यक्ष खण्डेलवाल ने दिव्यांगजन क्रिकेट महोत्सव नॉट आउट@100 के समापन कार्यक्रम को किया संबोधित

भोपाल।

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व विधायक हेमंत खण्डेलवाल ने दिव्यांगजन क्रिकेट महोत्सव ÷नॉट आउट@100÷ के समापन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि यह महोत्सव केवल एक खेल प्रतियोगिता नहीं, बल्कि साहस, आत्मविश्वास और अटूट संकल्प का जीवंत उदाहरण है। 100 घंटे के निरंतर क्रिकेट महोत्सव ने खेल जगत में एक नया इतिहास रच दिया है। इस अनूठे आयोजन में दिव्यांग खिलाड़ियों ने जिस जज्बे, धैर्य और हिम्मत का प्रदर्शन किया, वह अत्यंत प्रेरणादायक और सराहनीय है। उन्होंने कहा कि 100 घंटे तक लगातार क्रिकेट खेलना केवल एक रिकॉर्ड नहीं, बल्कि दृढ़ इच्छाशक्ति और आत्मबल का प्रतीक है। यह खेल महोत्सव को लिम्बा बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होना सभी के लिए गर्व की बात है। दिव्यांक खिलाड़ियों की प्रतिभा को दुनिया के सामने पहचान दिलाने के लिए इस तरह के आयोजन होना जरूरी हैं। समापन समारोह को मध्यप्रदेश के राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने भी संबोधित किया और खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दीं। राज्यपाल डॉ. मंगुभाई पटेल, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खण्डेलवाल ने राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान गाने वाली फाल्गुनी का मंच पर बुलाकर सम्मानित किया। समारोह में लिम्बा बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के प्रतिनिधियों ने राज्यपाल मंगुभाई पटेल और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खण्डेलवाल, डॉ. राघवेन्द्र शर्मा को इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट सौंपा। कार्यक्रम का स्वागत उद्बोधन व आयोजन समिति के मुख्य संयोजक डॉ. राघवेन्द्र शर्मा ने दिया। आभार राममनोहर सिंह ने व्यक्त किया। इस अवसर पर प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष उषा अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में खेल प्रेमी, खिलाड़ी और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। खिलाड़ियों की छिपी प्रतिभाओं को सामने लाने का कार्य है यह आयोजन भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खण्डेलवाल ने कहा कि दिव्यांग क्रिकेट खेल महोत्सव जैसे आयोजन प्रतिभाशाली दिव्यांग खिलाड़ियों को उचित मंच, सम्मान और अवसर प्रदान करते हैं और खिलाड़ियों को अपनी क्षमताओं को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का मार्ग प्रशस्त करते हैं।

हर खेत को मिलेगा पानी, एक लाख करोड़ के बजट से संवरेगा एमपी का किसान : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

भोपाल।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि सागर जिले के रहली क्षेत्र में कृषि आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन देते हुए फूड पार्क स्थापित किया जाएगा। इससे क्षेत्र के स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। बुंदेलखंड की धरती आल्हा-ऊदल जैसे वीरों की धरती है। सागर जिले का रहस मेला ऐतिहासिक है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव शुक्रवार को सागर जिले के गढ़ाकोटा के ऐतिहासिक रहस मेले के शुभारंभ एवं सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के हितग्राहियों के राशि अंतरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने रहस मेले के 217 साल पुराने गौरवशाली इतिहास को याद करते हुए और उनके शौर्य को प्रणाम करते हुए कहा -

बड़े लडैया महोबा वाले,
जिन की मार सही ना जाये।
एक को मारे दोई मर जावे,
तीजा खौफ खाये मर जाये।।

ऐसी वीरता और पराक्रम का लोहा मनवाने वाले मातृभूमि पर सर्वस्व न्योछावर करने वाले महान योद्धाओं की भूमि को कोटिशः नमन। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भारतीय संस्कृति में परमात्मा ने ऋतुओं और मौसम के साथ मेलों का अद्भुत संबंध बनाया है। जब धान और सोयाबीन कटे तो दीवाली और गेहूं की फसल आने पर होली मनाई जाती है। बुंदेलखंड की धरती पर आकर मन आनंदित हो जाता है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि किसान कल्याण वर्ष में कृषि आधारित व्यापार गतिविधियां बढ़ाने के लिए प्रयास जारी हैं, जिससे किसानों के

जीवन में समृद्धि आएगी। राज्य सरकार पशुपालन और दूध उत्पादन बढ़ाने को प्राथमिकता दे रही है। बजट 2026-27 में नई यशोदा योजना की शुरुआत की गई है। अब हमारे स्कूलों में 8वीं तक के विद्यार्थियों को ट्रेटा पैक दूध निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। प्रदेश की बहनों के सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। लाड़ली बहनों को हर माह 1500 रुपए की राशि मिल रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार लघु एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए संकल्पित है। रहली में सूक्ष्म औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए कमेटी गठित की जाए। यहां पारम्परिक बीड़ी उद्योग के साथ हस्त शिल्प कलाओं को भी आगे बढ़ाया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की माह जनवरी पेड इन फरवरी 2026 की राशि हितग्राहियों के खातों में सिंगल क्लिक से अंतरित की। इस पेंशन योजनाओं में प्रति हितग्राही प्रतिमाह 600 रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने 32.78 लाख से अधिक हितग्राहियों के खाते में 196.72 करोड़ की राशि ट्रांसफर की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने रहली विधासभा क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को मजबूती देते हुए खेजरा-शाहपुर-मोकलपुर फ्लाईओवर के निर्माण की स्वीकृति दी। उन्होंने रहली एवं गढ़ाकोटा कृषि उपज मंडी के उन्नयन के लिए 5-5 करोड़ रुपए एवं शाहपुर उपमंडी के विकास हेतु एक करोड़ रुपए की स्वीकृति दी जिससे स्थानीय किसानों को अपनी उपज का सही दाम और आधुनिक सुविधाएं मिल सकें इसके साथ ही उन्होंने रहली रमखरिया, सिमरिया नायक बहेरिया मढ़ि (लगभग 22 किलोमीटर) मार्ग के उन्नयन और चौड़ीकरण की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि बुंदेलखंड में बीड़ी उद्योग और तेंदूपत्ता संग्रहण केवल व्यापार नहीं, बल्कि लाखों परिवारों की जीविका रहा है। यहां बीड़ी, तेंदूपत्ते और हस्तकला आधारित लघु इकाइयों को मिलेगा प्रोत्साहन दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बीड़ी बनाने वाले एवं तेंदूपत्ता का संग्रहण करने वाले व्यक्तियों के उन्नयन के लिए सांसद, विधायक एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि एक कमेटी बनाकर लिये गये निर्णय अनुसार कार्यवाही की जाएगी। इसके साथ ही क्षेत्र के खिलाड़ियों के लिए स्पोर्ट्स एवं स्टेडियम कॉम्प्लेक्स का निर्माण होगा।

भारत साम्राज्य, भोपाल। राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने सीधी जिले के ग्राम परसिली में प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना के हितग्राही ओम प्रकाश बैगा के परिजनों से आत्मीय संवाद कर शासन की अन्य योजनाओ के लाभों के संबंध में जानकारी प्राप्त की।

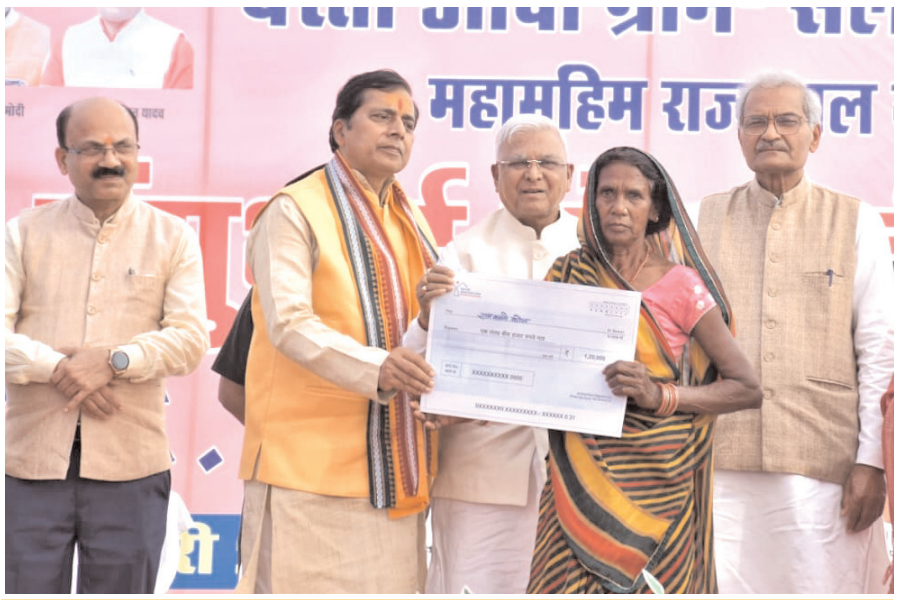

भारत साम्राज्य, भोपाल। राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने मऊगंज जिले के ग्राम सलैया खास में धरती आबा जनजातीय ग्राम में विभिन्न योजना के हितग्राहियों को हितलाभ वितरित किए।

मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस ने कहा बगैर मुआवजे के खदान चालू हो गई, सरकार बोली सिर्फ पेड़ काटे और मिट्टी हटाई

संयुक्त जांच समिति की मांग पर हंगामा, दो बार कार्यवाही स्थगित

भोपाल।

मध्य प्रदेश विधानसभा में आज गुरुवार को प्रश्नकाल के दौरान जमकर हंगामा हुआ। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने कहा कि सिंगरौली जिले की धरौली कोयला खदान मामले में उचित मुआवजा दिए बगैर सरकार ने खदान चालू करवा दी। अडानी की इस खदान से जो लोग प्रभावित हुए हैं वो दर-दर की ठोकरें खा रहे है। और सरकार ने पुलिस अफसरों को मुआवजा बांट दिया। इसके लिए विधानसभा की संयुक्त समिति से जांच होना चाहिए। बजट सत्र में विपक्ष की इस मांग पर सरकार ने सटीक जवाब नहीं दिया तो विपक्षी सदस्यों ने आसंदी के सामने आकर नारेबाजी की। बढ़ते हंगामे के बीच विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को दो बार सदन की कार्यवाही स्थगित करना पड़ी।

दरअसल गुरुवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सिंगरौली जिले की धरौली कोयला खदान का मामला उठाते हुए कहा कि सरकार ने वादा किया था भूमि अधिग्रहण के प्रभावितों को 50-50 लाख का मुआवजा देंगे। लेकिन हकीकत यह है कि वहां सिर्फ दो से लाख ढाई की ही राशि बतौर मुआवजा दी गई है। कुल आठ गांव प्रभावित हुए थे जिसमें में सरकार ने मात्र 5 गांवों के ग्रामीणों को ही मुआवजा दिया है। और तो और इससे ज्यादा अंधेर क्या होगा कि वहां कुछ थाना प्रभारी स्तर के पुलिस अफसरों को मुआवजा दे दिया गया। और आदिवासी समाज के लोग वंचित रह गए। इस पर राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने जबाव देते हुए कहा कि इस मामले की जांच करवा लेंगे और समाधान कर लेंगे। इस पर सिंघार ने कहा कि मंत्री प्रहलाद पटेल के नेतृत्व के एक विधानसभा की संयुक्त समिति बनाकर उससे जांच करा लें। इस पर सरकार तैयार होती नहीं दिखी तो कांग्रेस के सदस्यों ने हंगामा शुरु कर दिया। विधायक सचिन यादव, रजनीश सिंह, जयवर्धन सिंह सहित कई

सदस्य आसंदी के सामने आ गए और नारेबाजी करने लगे। बढ़ते शोर शराबे के बीच विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने 10 मिनिट के लिए सदन की कार्यवाही स्थिगित कर दी।

इसके बाद दूसरी बाद सदन की कार्यवाही शुरु हुई तो तब भी विपक्षी दल कांग्रेस नारेबाजी करता रहा। स्पीकर तोमर ने उन्हे शांत होने और अपनी अपनी सीट पर बैठ जाने को कहा। इस पर कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक भंवर सिंह शेखावत ने कहा कि अध्यक्ष महोदय, ये सदन आपके निर्देश पर ही चलता है आप कह रहे हैं कि बैठ जाओ तो बैठ जाएंगे आप कहेंगे खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाएंगे लेकिन सरकार स्थिति को स्पष्ट क्यों नहीं कर रही है। आपके मंत्री के ही नेतृत्व हम लोग जांच कराना चाहते हैं क्या सरकार को अपने मंत्री पर भरोसा नहीं है। यदि है तो जांच कराने में कौन सी दिक्कत है। इस पर अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हमे प्रभारी मंत्री की बात सुनना चाहिए वो भी कुछ कहना चाहतीं हैं। इस पर मंत्री संपतिया उइके ने कहा कि मैं उस जगह पर दो बार गई हूं वहां 33000 पेड़ काटे गए हैं, कुछ मिट्टी हटाई गई है, अभी खदान चालू नहीं हुई है। इस पर कांग्रेस के सदस्य भड़क गए उन्होंने कहा इसका मतलब है खदान चालू हो गई यही तो खदान का शुरुआती काम होता है। अब संशय कहां कि खदान चालू नहीं हुई है।

● थाना प्रभारी को 15,94,990 का मुआवजा

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि कोल ब्लॉक के लिए 8 गांवों की जमीन अधिग्रहित की जा रही है और कलेक्टर की सूची के अनुसार 12,998 परिवार प्रभावित हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रभावित आदिवासी परिवारों को पूरा मुआवजा नहीं मिला है। लेकिन थाना प्रभारी जितेंद्र भदौरिया की पत्नी को 15,94,990 रुपए और यातायात प्रभारी दीपेंद्र सिंह कुशवाह की पत्नी स्वाति सिंह के नाम पर 14,42,482 रुपए मुआवजा दिया गया। उन्होंने इस मामले की विधानसभा समिति से जांच कराने की मांग की।

● खदान वाले क्षेत्र को छावनी बना दिया

तभी नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि हम लोग वहां जाना चाहते थे लेकिन जैसे ही खबर लगी की कांग्रेस के कुछ विधायक खदान देखने जा रहे हैं वहां 4 हजार सुरक्षाकर्मी तैनात कर दिए गए। पूरे क्षेत्र को छावनी बना दिया गया। मंत्रीजी पेड़ काटने की बात कह रहीं हैं उन पेड़ों को छत्तीसगट भेजा जा रहा है। ये मप्र के के साथ अन्याय है। इस पर कांग्रेस विधायकों ने फिर हंगामा शुरु कर दिया और अडानी की सरकार नहीं चलेगी के नारे लगाने लगे। इस बीच अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर सदस्यों के शांत करते रहे और नियमों का हवाला देते रहे लेकिन उनकी किसी ने एक नहीं सुनी। भारी शोर शराबे को देखते हुए अध्यक्ष ने 12 बजे तक के लिए विधानसभा की कार्यवाही स्थिगित कर दी।

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक नागेश नरवरिया द्वारा जय माता प्रिंटर्स म.नं. 1 अमर दाल मिल के पास पेमदीपुरा चिकलोद रोड के पास बापू कालोनी जहांगीराबाद भोपाल मप्र से मुद्रित एवं म.नं. 51 एक्सटेंशन शिवलोक कॉलोनी फेस-3, खजूरी कलां रोड, तह. हुजूर जिला भोपाल से प्रकाशित। **संपादक** : नागेश नरवरिया (समस्त विवादों का न्यायक्षेत्र भोपाल रहेगा।)